दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 ‖ Postal Registration No-055/Raigarh DN CG ‖ रायगढ़, बुधवार 28 जुलाई 2021 ‖ पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए ‖ वर्ष-03, अंक- 298

महत्वपूर्ण एवं खास

दिल्ली में बारिश से सड़के बनी दरिया, ट्रैफिक जाम

नई दिल्ली (आरएनएस)। आज लगातार बारिश से दिल्ली के लोगों को उमस भरे मौसम से काफी राहत मिली, हालांकि शहर के प्रमुख चौराहों पर जलभराव के कारण जाम की स्थिति बनी रही। मौसम विभाग ने अगले 2 घंटों के दौरान राष्ट्रीय राजधानी के साथ-साथ गुरुग्राम, मानेसर, पानीपत (हरियाणा) और आसपास के क्षेत्रों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम तीव्रता की गरज के साथ बारिश होने की भविष्यवाणी की है। आईएमडी ने मंगलवार को तड़के ट्वीट किया उत्तर-पश्चिम दिल्ली, मध्य दिल्ली, दक्षिण-दिल्ली, दक्षिण-पश्चिम-दिल्ली, गुरुग्राम, मानेसर, सोहना, भिवाड़ी, बावल, नारनौल, कोसली, रेवाड़ी, नूंह, मानेसर (हरियाणा), तिजारा, अलवर, राजगढ़, डीग, नगर, खैरथल, मेहंदीपुर, महवा, लछमनगढ़, नदबई (राजस्थान) और आसपास के क्षेत्रों में अगले 2 घंटों के दौरान कई स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश होगी। दूसरी ओर, बारिश के कारण जलजमाव से दिल्ली के कई इलाकों में यातायात जाम हो गया है। दिल्ली के प्रगति मैदान और मथुरा रोड पर एक ऑटो-रिक्शा फंस गया और कई कारें और बसें आंशिक रूप से जलमग्न हो गई। ट्रैफिक पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि, जलभराव के कारण आईपी फ्लाईओवर के पास डब्ल्यूएचओ बिल्डिंग के सामने यातायात प्रभावित हुआ है।

महाराष्ट्र 1 करोड़ लोगों का पूर्ण टीकाकरण करने वाला बना पहला राज्य

मुंबई (आरएनएस)। महाराष्ट्र एक करोड़ से अधिक लोगों को कोविड से बचाव का टीका पूरी तरह लगाने की बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) प्रदीप व्यास ने कहा, यहां कोविड-19 वैक्सीन की दोनों खुराक पाने वालों की कुल संख्या आज (सोमवार) शाम 4 बजे तक 1,00,64,308 हो गई, बड़ी उपलब्धि है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने एक करोड़ से अधिक आबादी को टीके की दोनों खुराक लगाने के रिकॉर्ड आंकड़े तक पहुंचने के लिए स्वास्थ्य विभाग के प्रयासों की सराहना की। टोपे ने कहा कि राज्य में अब तक 3,16,09,227 लोगों को पहली खुराक लगाई जा चुकी है और राज्य ने रविवार तक कुल 4,13,19,105 टीकाकरण (पहली और दूसरी खुराक) में सफलता पा ली है। राज्य के 36 जिलों में लगभग 4,100 केंद्रों पर सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में प्रतिदिन औसतन 100,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण हो रहा है।

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ताजिकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में लेंगे हिस्सा

नई दिल्ली (आरएनएस)। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह 27 जुलाई से 29 जुलाई, 2021 तक दुशांबे, ताजिकिस्तान के दौरे पर रहेंगे, जहां वे शंघाई सहयोग संगठन (शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाईजेशन - एससीओ) सदस्य देशों के रक्षामंत्रियों की वार्षिक बैठक में हिस्सा लेंगे। वार्षिक बैठक में एससीओ सदस्य देशों के बीच रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा होगी और बातचीत के बाद बयान भी जारी हो सकता है। राजनाथ सिंह बैठक को 28 जुलाई, 2021 को सम्बोधित करेंगे।

चंबा के पास कई जगह टूटा ऋषिकेश-धरासू हाईवे

नई दिल्ली (आरएनएस)। उत्तराखण्ड के ऋषिकेश में पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजना आल वेदर सड़क घटिया निर्माण के चलते सीजन की पहली बरसात भी नही झेल पाई। सड़क पर जगह-जगह भू धसाव होने के कारण क्षतिग्रस्त हो गई है। ग्रामीणों ने शासन-प्रशासन से हाईवे पर हुये निर्माण कार्य की जांच की मांग की है। ऋषिकेश-धरासू राष्ट्रीय राजमार्ग -94 के अंतर्गत चंबा के समीप करीब 86 करोड़ की लागत से ऑस्ट्रेलियन तकनीक से बनी लगभग एक किमी लंबी आलवेदर सड़क जिसमें में 440 मीटर लंबी टर्नल भी शामिल है, जिसका का कार्य दिसम्बर 2020 में पूर्ण हो चुका है, लेकिन अभी इस सड़क और सुरंग का लोकापर्ण नहीं हो पाया है।

नीट में ओबीसी आरक्षण लागू करने की तैयारी में सरकार

» राज्यों को अपने नियम के अनुसार कोटा लागू करने का दे सकती है निर्देश

» एनडीए की बैठक में अनुप्रिया के बाद अब राज्यसभा में सुशील मोदी ने उठाया मुद्दा

» स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाईकोर्ट की कमेटी के समक्ष कोटा लागू करने का किया समर्थन

नई दिल्ली ,27 जुलाई (आरएनएस)। इस साल राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) ऑल इंडिया कोटा में ओबीसी आरक्षण लागू हो सकता है। इस मामले में विभिन्न स्तरों से फीडबैक हासिल करने के बाद केंद्र सरकार इस संबंध में जल्द फैसला लेने की तैयारी कर रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाईकोर्ट से जुड़ी कमेटी में ओबीसी कोटा लागू करने का समर्थन किया है। गौरतलब है कि मानसून सत्र से पहले हुई राजग और सर्वदलीय बैठक में वाणिज्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने यह मामला उठाया था।

उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक शीर्ष स्तर पर नीट में राज्य और राज्यों के मेडिकल कॉलेज में ओबीसी आरक्षण लागू न होने केमामले में कई बार मंथन हुआ है। खासतौर पर अगले साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश सहित पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के संदर्भ में भी इस पर चर्चा हुई। कई स्तर पर फीडबैक हासिल करने के बाद सरकार ने ओबीसी कोटा लागू करने केलिए कदम उठाने का मन बना लिया है। इसके तहत राज्यों को अपने अपने राज्य के नियमों के अनुसार ओबीसी कोटा लागू करने का निर्देश दिया जा सकता है। गौरतलब है कि वर्तमान में ओबीसी कोटा सिर्फ केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ही लागू है। विभिन्न राज्य और निजी मेडिकल कॉलेज एसटी, एसटी और आर्थिक रूप से पिछड़ों को 15 फीसदी कोटा दिया जा रहा है।

अनुप्रिया के बाद सुशील मोदी ने उठाया मामला- नीट में ओबीसी आरक्षण मामले में राजग की सहयोगी अपना दल की अध्यक्ष और वाणिज्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के बाद मंगलवार को राज्यसभा में सुशील मोदी ने आवाज उठाई। अनुप्रिया ने 18 जून को हुई सर्वदलीय और राजग की अलग-अलग बैठकों में प्रधानमंत्री के समक्ष यह मामला उठाया था। इसके अलावा उन्होंने गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को व्यक्तिगत स्तर पर भी पिछड़ा वर्ग में नाराजगी का हवाला देते हुए इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की थी। इसके बाद मंगलवार को राज्यसभा में भाजपा सांसद सुशील मोदी ने भी नीट में ओबीसी कोटा बहाली की मांग की।

केंद्र-स्वास्थ्य मंत्रालय का सकारात्मक रुख- सूत्रों का कहना है कि इस विवाद मामले में हाईकोर्ट द्वारा गठित कमेटी के समक्ष स्वास्थ्य मंत्रालय ने सकारात्मक रुख अपनाया। मंत्रालय ने कमेटी से कहा कि वह ओबीसी कोटा लागू करने के पक्ष में है।

देश में चार माह बाद कोरोना पर बड़ी राहत

» 24 घंटों में 29,689 नए मामले, 415 मरीजों की मौत

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार उतार-चढ़ाव में बीच पिछले चार महीने बाद ऐसा मौका आया है, जब एक दिन में तीस हजार से कम संक्रमण के मामले सामने आए हैं। यानि पिछले 24 घंटे में कोरोना के मामलों में भारी गिरावट के बाद 29,689 नए मामले दर्ज किये गये, जबकि संक्रमण की वजह से 415 मरीजों ने इस दौरान अपनी जान गंवाई है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इससे पहले मार्च 2021 में कोरोना के नए मामले तीस हजार से कम आए थे, जिसके बाद लगातार बढ़ते गये और दूसरी लहर में यह आंकड़ा चार लाख से अधिक दैनिक मामले पहुंच गये थे। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में कुल 29,689 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 415 लोगों की मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 42,363 लोग कोरोना संक्रमण को मात देकर ठीक भी हुए हैं। इस प्रकार देश में रिकवरी रेट 97.39 प्रतिशत पर पहुंचा गया है यानि अब तक देश में 3,06,21,469 मरीज ठीक हुए हैं। इस वक्त देश में 3,98,100 मरीज कोरोना से संक्रमित हैं, जबकि कुल मौत का आंकड़ा 4,21,382 पहुंच चुका है। । देश की कोरोना से मृत्यु दर 1.34 फीसदी है। आंकड़ों के मुताबिक भारत में कुल 3,14,40,951 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं।

इन पांच राज्यों में जारी कोरोना का कहर- देश में जहां कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ देश के पांच राज्यों केरल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले देखने को मिल रहे हैं। चिंताजनक पहलू ये है कि इन राज्यों में टेस्टिंग और वैक्सीनेशन में भी कमी देखी गई है।

पिछले दो साल में नक्सली घटनाओं में 625 लोगों की मौत

नई दिल्ली (आरएनएस)। सरकार ने मंगलवार को बताया कि देश में 2018 से 2020 के दौरान तीन वर्ष की अवधि में नक्सलवादी गतिविधियों/ वामपंथी उग्रवाद की 2,168 घटनाओं में 625 लोगों की मौत हो गयी।

यह जानकारी लोकसभा में लल्लू सिंह और नितेश गंगा देव के सवालों के जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने यह जानकारी दी। गृह राज्य मंत्री ने कहा कि पिछले तीन वर्ष में नक्सलवादी गतिविधियों/वामपंथी उग्रवाद की गतिविधियों में कमी आई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 में ऐसी 833 घटनाओं में 240 लोगों की मौत हुई जबकि 2019 में 670 इस तरह की घटनाओं में 202 मौतें तथा 2020 में 665 घटनाओं में 183 लोगों की मृत्यु हुई।

एक अन्य प्रश्न के जवाब में नित्यानंद राय ने कहा कि राज्य पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों द्वारा चलाये गए एक संयुक्त अभियान के दौरान 3 अप्रैल, 2021 को छत्तीसगढ़ के सुकमा के पुलिस स्टेशन जगरगुंडा में वामपंथी उग्रवादियों के साथ गोलीबारी में 22 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए जिनमें सीआरपीएफ के 8 और पुलिस के 14 कर्मी शामिल हैं। गृह राज्य मंत्री ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद के खतरे का मुकाबला करने के लिये भारत सरकार ने 2015 में राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना तैयार की है जिसमें सुरक्षा संबंधी उपाय, विकास परक पहल और स्थानीय समुदायों के अधिकार एवं हकदारियां सुनिश्चित करने का बहु आयामी दृष्टिकोण शामिल है।

भीख मांगना सामाजिक-आर्थिक मसला : सुप्रीम कोर्ट

» हम सामंतवादी दृष्टिकोण नहीं अपना सकते

नई दिल्ली ,27 जुलाई (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भीख मांगना एक सामाजिक और आर्थिक मसला है और गरीबी, लोगों को भीख मांगने के लिए मजबूर करती है। यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें कोविड-19 महामारी के दौरान सार्वजनिक स्थलों व सड़कों पर भीख मांगने पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने कुश कालरा द्वारा दायर इस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा कि वह भीख मांगने पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर विचार नहीं कर सकती। पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील से सवाल किया कि आखिर लोग भीख क्यों मांगते हैं? गरीबी के कारण लोग भीख मांगने को मजबूर होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब गरीबी भीख मांगने के लिए मजबूर करती है तो वह संभ्रांतवादी दृष्टिकोण नहीं अपनाएगा। कोई भीख नहीं मांगना चाहेगा, गरीबी के कारण उन्हें ऐसा करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है, यह एक सामाजिक-आर्थिक समस्या है। यह सरकार की आर्थिक व सामाजिक नीति का एक हिस्सा है। हम यह नहीं कह सकते कि वे(भिखारी) हमारी आंखों से दूर हो जाएं।

केंद्र व दिल्ली सरकार को नोटिस- पीठ ने कहा कि अगर हम इस मामले में नोटिस जारी करते हैं तो इसका मतलब यह समझा जाएगा कि हम ऐसा करना चाहते हैं। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट याचिकाकर्ता की उस मांग पर सरकार को नोटिस जारी किया है जिसमें भिखारियों के पुनर्वास और टीकाकरण की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र व दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है।

इंडियन पैनोरामा की प्रविष्टि की अंतिम तिथि हुई 12 अगस्त

नई दिल्ली (आरएनएस)। प्रविष्टियों की अंतिम तिथि निकट आती जा रही है, जिसके साथ ही 52वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आईएफएफआई) ने इंडियन पैनोरामा, 2021 की प्रविष्टि के लिये दोबारा आह्वान किया है। उल्लेखनीय है कि इंडियन पैनोरामा आईएफएफआई का प्रमुख अंग है, जिसके तहत फिल्म कला को प्रोत्साहन देने के लिये सर्वश्रेष्ठ समकालीन भारतीय फिल्मों का चयन किया जाता है।

18 जुलाई, 2021 से आईएफएफआई के लिये प्रविष्टियां भेजने का सिलसिला शुरू हुआ था। महोत्सव गोवा में 20 से 28 नवंबर, 2021 तक चलेगा।

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 अगस्त, 2021 है, और अन्य

जरूरी दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन दी जाने वाले आवेदन की हार्ड कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 23 अगस्त, 2021 है। वर्ष 2021 के इंडियन पैनोरामा के लिये फिल्में जमा करने के लिये तयशुदा दिशा-निर्देश हैं। जमा की गई फिल्म का निर्माण पूरा होने या केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) की तारीख, महोत्सव शुरू होने से साल भर पहले की होनी चाहिये, यानी एक अगस्त, 2020 से 31 जुलाई, 2021 की मियाद के बीच। जिस फिल्म के पास सीबीएफसी का प्रमाणपत्र नहीं होगा, लेकिन उसका निर्माण इस अवधि के भीतर पूरा हो चुका है, तो वह फिल्म भी जमा की जा सकती है। सभी फिल्मों में अंग्रेजी में सब-टाइटल्स होना जरूरी है।

वर्ष 1978 में भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के अंग के रूप में इंडियन पैनोरामा को शुरू किया गया था, जिसका मकसद था भारतीय फिल्मों और भारतीय फिल्मों के माध्यम से भारत की समृद्ध संस्कृति और विरासत को प्रोत्साहन देना। इसके बाद से ही इंडियन पैनोरामा पूरी तरह आयोजन वर्ष के दौरान बेहतरीन भारतीय फिल्मों को पेश करने में पूरी तरह समर्पित रहा।

उल्लेखनीय है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय का फिल्म महोत्सव विभाग इंडियन पैनोरामा का आयोजन करता है। इसके तहत सिनेमाई, विषय आधारित और सौंदर्यबोधक उत्कृष्टता वाली फीचर तथा गैर-फीचर फिल्मों का चयन किया जाता है। इसके जरिये भारत और विदेश में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सवों में फिल्में पेश करके फिल्म कला को प्रोत्साहन दिया जाता है। महोत्सवों में फिल्मों से कोई कमाई नहीं की जाती है। इसके अलावा द्विपक्षीय आदान-प्रदान कार्यक्रम और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के तहत विशेष भारतीय फिल्म महोत्सवों तथा भारत में विशेष इंडियन पैनोरामा के जरिये भी फिल्म कला को प्रोत्साहन दिया जाता है।

पोर्न फिल्म मामला : राज कुंद्रा को 10 अगस्त तक न्यायिक हिरासत

मुंबई (आरएनएस)। सनसनीखेज पोर्न फिल्म रैकेट मामले में मुख्य आरोपी कारोबारी राज कुंद्रा को 10 अगस्त तक दो सप्ताह की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उनके वकील अबाद पोंडा ने मंगलवार को यहां यह जानकारी दी।

बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति कुंद्रा को मुंबई की एक अदालत में पेश किया गया, जिसने उनकी पुलिस हिरासत को और सात दिनों के लिए बढ़ाने की अभियोजन की याचिका को खारिज कर दिया।

पोंडा ने कहा कि कुंद्रा की जमानत अर्जी पर बुधवार को मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में सुनवाई होगी।

कुंद्रा को मुंबई पुलिस ने पिछले सोमवार को अश्लील सामग्री बनाने और बांटने के सनसनीखेज मामले में गिरफ्तार किया था।

उन पर भारतीय दंड संहिता, आईटी अधिनियम और महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत अपराध का आरोप लगाया गया है।

गिरफ्तारी के तुरंत बाद, उन्हें 23 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया, जिसे 27 जुलाई तक बढ़ा दिया गया था। अब उन्हें 10 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

2022 तक सौर ऊर्जा से एक लाख मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य

» एमएसएमई सेक्टर को होगा फायदा

नई दिल्ली (आरएनएस)। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन अब पूरे देश में सोलर एनर्जी के माध्यम से बिजली बचत की मुहिम शुरू करेगा। इसके लिए एसोसिएशन ने सोलर एनर्जी एंड ई-व्हीकल कमेटी के चेयरमैन को जिम्मेदारी दी है। एसोसिएशन ने कमेटी के चेयरमैन के तौर पर तारिक हसन नकवी को नियुक्त किया है। नकवी ने बताया कि उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि 2022 तक सोलर एनर्जी का तय लक्ष्य ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में

हासिल किया जाए। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए नकवी ने पूरा रोडमैप भी तैयार कर लिया है।

सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बीते लंबे समय से काम कर रहे विशेषज्ञ तारिक हसन नकवी ने बताया कि केंद्र सरकार का लक्ष्य 2022 तक सोलर एनर्जी के माध्यम से एक लाख मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य है। जबकि उत्तर प्रदेश में यही लक्ष्य 2022 तक 10700 मेगावाट का है। रिजवी कहते हैं कि सोलर एनर्जी से एमएसएमई को सबसे ज्यादा फायदा होगा। उन्होंने कहा लेकिन सरकार की कुछ नीतियों के चलते इसका अभी लाभ लघु एवं मध्यम उद्योग को नहीं मिल पा रहा है। वह कहते हैं कोविड के दौरान यह इंडस्ट्री चरमरा गई है। उनका कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से इस इंडस्ट्री को सोलर एनर्जी के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के सोलर एनर्जी एंड ई-व्हीकल कमेटी के चेयरमैन नकवी कहते हैं दरअसल लघु एवं मध्यम उद्योग में नेट मीटरिंग व्यवस्था को बंद कर दिया गया है। इस व्यवस्था में सोलर एनर्जी के माध्यम से जितनी बिजली ग्रिड में जाती थी उतने यूनिट बिजली का वित्तीय लेखा-जोखा वित्तीय वर्ष के अंत में किया जाता था। रिजवी के मुताबिक जितनी बिजली ग्रिड में जाती थी उसका बिल बिजली विभाग के बिल के साथ एडजस्ट किया जाता था। अब इस व्यवस्था को फिलहाल लघु एवं मध्यम उद्योग के लिए बंद कर दिया गया है। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के मुताबिक लघु एवं मध्यम उद्योग को बढ़ावा मिले इसलिए नेट मीटरिंग व्यवस्था को दोबारा चालू किया जाना चाहिए। इसके लिए उनका संगठन केंद्र और राज्य सरकार पर लगातार ना सिर्फ दबाव बना रहा है बल्कि संबंधित महकमे और अधिकारियों से संपर्क में भी है। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के मुताबिक उनकी पूरी कोशिश है उनके संगठन से जुड़े हजारों उद्यमी सोलर एनर्जी के माध्यम से देश में लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करें। इसके लिए उनके संगठन की बनाई गई नई कमेटी सभी उद्यमियों की न सिर्फ मदद करेगी बल्कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के साथ मिलकर एक पुल के तौर पर काम भी करेगी।